

यूपी में आंधी-तूफान से 96 मौतें

► आंधी-बारिश और हीटवेव का कहर, कई राज्यों में अलर्ट

नई दिल्ली, 14 मई. देशभर में मौसम का मिजाज बेहद खतरनाक और असामान्य बना हुआ है. उत्तर भारत के कई राज्यों में जहां तेज आंधी-तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी है, वहीं पश्चिम और मध्य भारत भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में हैं. उत्तर प्रदेश में बुधवार को आए तेज तूफान और आंधी ने भारी जनहानि की. प्रयागराज, अयोध्या समेत 30 जिलों में 96 लोगों की मौत हो गई. सबसे ज्यादा 21 मौतें प्रयागराज और 17 भदोही में दर्ज की गईं.

कई इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं.



बरेली में तेज आंधी के दौरान एक युवक टीनशेड समेत हवा में उड़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मौसम विभाग ने आज भी यूपी के 51 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. दूसरी तरफ राजस्थान में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. जैसलमेर लगातार चौथे दिन देश का सबसे गर्म शहर बना रहा,

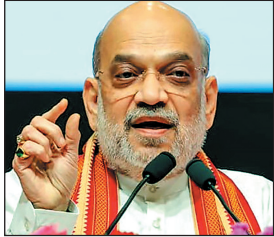
जहां अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 जिलों में हीटवेव की चेतावनी दी गई है।मध्य प्रदेश में भी हालात गंभीर हैं. राज्य के 25 से ज्यादा जिलों में हीटवेव का असर जारी है, जो 18 मई तक बना रह सकता है. खजुराहो में बुधवार को तापमान

45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां गर्म रातों यानी वार्म नाइट की भी चेतावनी दी गई है. हरियाणा में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है. नारनौल में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. राज्य में 17 मई से हीटवेव का यलो अलर्ट लागू रहेगा।मौसम विभाग के मुताबिक 16 मई को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. वहीं जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना है. बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली गिरने और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया .

ऑनलाइन गेमिंग फंड रूटिंग मामले

नयी दिल्ली, 14 मई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत, चाइगाई टेकनोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़े एक कथित ऑनलाइन गेमिंग फंड रूटिंग मामले के सिलसिले में 14 व्यक्तियों और संस्थाओं के परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया. ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि यह तलाशी दिल्ली, गुजरात, इंदौर और श्रीनगर में ली गयी गयी. अधिकारियों के अनुसार चाइगाई टेकनोलॉजीज़ द्वारा कथित तौर पर ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए पेमेंट एग्रीगेटर्स के जरिए व्यक्तियों से निधि इकट्ठा करने के बारे में जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की गयी.

हीटवेव मौतों को शून्य करने की तैयारी : शाह



नयी दिल्ली 14 मई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण को 'मिनिमम कैजुअल्टी' से 'ज़ीरो कैजुअल्टी' तक लाने के साथ-साथ लू से होने वाली मृत्यु दर को शून्य तक लाने की दिशा में कार्य कर रही है. शाह ने गुरुवार को गाज़ियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ('एनडीआरएफ') को 'प्रेसिडेंट्स क्लर' प्रदान किए जाने के समारोह में यह बात कही.

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बल की उपलब्धियों की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने अब तक डेढ़ लाख से अधिक लोगों की जान बचाई है और नौ लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा हो या

भौषण हादसा, बल ने हर चुनौती में अपनी दक्षता साबित की है. उन्होंने एनडीआरएफ को मिले 'प्रेसिडेंट्स क्लर' को बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण का राष्ट्रीय सम्मान बताया. शाह ने कहा कि यह सम्मान केवल एनडीआरएफ की सेवाओं की मान्यता नहीं, बल्कि देशभर में आपदा प्रबंधन से जुड़े पूरे तंत्र के सामूहिक योगदान का सम्मान है. एनडीआरएफ ने बीते 20 वर्षों में अपने साहस, सेवा और त्वरित कार्रवाई से 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास अर्जित किया है.

गृह मंत्री ने कहा कि देश ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में राहत-आधारित व्यवस्था से आगे बढ़कर रोकथाम और तैयारी आधारित मॉडल अपनाया है. उन्होंने दावा किया कि सरकार अब 'ज़ीरो कैजुअल्टी' यानी आपदाओं में शून्य जनहानि के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि मौसम पूर्वानुमान और शुरुआती चेतावनी प्रणालियों को मजबूत कर जन-धन के नुकसान को न्यूनतम करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार लू यानी हीट वेव से होने वाली मृत्यु दर को शून्य तक लाने की दिशा में कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ ने भारत को वैश्विक स्तर पर आपदा प्रबंधन में अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है.

एनआईए ने दस आरोपियों पर कसा शिकंजा

► लाल किला बम केस में चार्जशीट दाखिल

► 7500 पन्नों संग एनआईए की बड़ी कार्रवाई

नयी दिल्ली 14 मई. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने लाल किला क्षेत्र में हुए कार बम विस्फोट मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ 7500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है जिसमें 11 लोगों की मौत हो गयी थी और कई लोग घायल हुए थे. पिछले साल 10 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में एक कार में लगे शक्तिशाली विस्फोटक उपकरण विस्फोट से इलाके में भारी तबाही हुई थी और आसपास की संपत्ति को भी व्यापक नुकसान पहुंचा था. पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एनआईए की विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट के अनुसार 10 आरोपियों में मुख्य साजिशकर्ता डॉ. उमर उन नबी भी शामिल है



जिसकी विस्फोट के दौरान मौत हो गयी थी. वह आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़ा हुआ था. यह संगठन भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा का एक सहयोगी गुट है. गृह मंत्रालय ने जून 2018 में एक्ज्यूटिव्स और उससे जुड़े सभी संगठनों को अंतःकवादी संगठन घोषित किया था. चार्जशीट गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967, भारतीय न्याय संहिता 2023, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, शस्त्र अधिनियम 1959 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 को विभिन्न धाराओं के तहत दाखिल की गई है.

मुख्य साजिशकर्ता पुलवामा निवासी डॉ. उमर उन नबी हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मेडिसिन विभाग में सहायक प्रोफेसर रह चुका था. उसकी मौत हो चुकी है और उसके खिलाफ कार्रवाही समाप्त करने का प्रस्ताव अदालत में रखा गया है. आरोपपत्र में में अमिर राशिद मीर, जासिर बिलाल यानी, डॉ. मुजमिल शकील, डॉ. आदिल अहमद रादर, डॉ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद वागे, सोयाब, डॉ. बिलाल नसीर मल्हा और यासिर अब्दमद डार को भी आरोपी बनाया गया है. जांच के दायरे में जम्मू-कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर, गुजरात और दिल्ली-एनसीआर के कई इलाके आये. एजेंसी ने 588 मौखिक गवाहियों, 395 से अधिक दस्तावेजों और 200 से ज्यादा जल सामग्री को साक्ष्य के रूप में चार्जशीट में शामिल किया है.

दिल्ली सरकार ने सरकारी वाहनों के उपयोग में की कटौती

► कारपूलिंग और मेट्रो उपयोग पर जोर

नई दिल्ली, 14 मई। नई दिल्ली में ऊर्जा संरक्षण और पेट्रोल-डीजल की बचत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी वाहनों के उपयोग को सीमित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों कार्यो के लिए न्यूनतम वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा।

इसके साथ ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जनता से भी अपील की कि वे निजी वाहन कम उपयोग करें और मेट्रो तथा डीटीसी बसों का अधिक से अधिक उपयोग करें। मेट्रो अब

416 किलोमीटर लंबा नेटवर्क संचालित कर रही है, जिसमें 303 स्टेशन और 343 ट्रेनें प्रतिदिन 4,500 से अधिक फेरे चला रही हैं। यह नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और बहादुरगढ़ सहित एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में 65 लाख से अधिक यात्रियों की सेवा प्रदान करती है।

डीटीसी का कुल 6,300 बसों का बेड़ा संचालित हो रहा है, जिसमें 4,538 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इनमें 9 मीटर की 1,593 देवी बसें, 12 मीटर की 2,845 इलेक्ट्रिक बसें और 100 फीडर बसें शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2026 तक इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ाकर 7,500 और वर्ष 2028 तक 14,000 करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो और डीटीसी बसों के विस्तार से यात्रा का समय कम हुआ है, प्रदूषण में कमी आई है.

16 राज्यों में एसआईआर का अगला चरण शुरू

► तीन केंद्रशासित प्रदेशों में बढ़ेगा एसआईआर अभियान

नई दिल्ली, 14 मई. भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत करने की घोषणा की. आयोग ने कहा कि यह एक बड़ा देशव्यापी अभियान होगा, जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों की सटीकता और पारदर्शिता को मजबूत करना है.

एसआईआर के तीसरे चरण का कार्यक्रम वर्तमान में जनगणना के तहत चल रहे मकाओं की सूचीकरण प्रक्रिया में लगी साझा फोल्ड मशीनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है. तीसरे चरण की शुरुआत के साथ एसआईआर प्रक्रिया पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी, हालांकि इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल नहीं

होंगे. आयोग ने कहा कि इन तीन क्षेत्रों का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा. यह निर्णय जनगणना के दूसरे चरण के पूरा होने और ऊंचाई वाले तथा बर्फ से ढके क्षेत्रों में मौसम संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे इस संशोधन अभियान के तहत 3.94 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) गणना चरण में लगभग 36.73 करोड़ मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे. इन बीएलओ की मदद विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नामित

लगभग 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) करेंगे। इसीआई ने एसआईआर को एक 'सहभागी और पारदर्शी प्रक्रिया' बताया है, जिसमें कई स्तरों पर मतदाता, राजनीतिक दल और चुनाव शामिल होते हैं. राजनीतिक भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे संशोधन प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता, समावेशिता और प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए हर मतदान केंद्र पर बूथ स्तर के एजेंट नियुक्त करें।

ज्ञानेश कुमार ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के तीसरे चरण की शुरुआत के अवसर पर कहा, 'मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वे एसआईआर के तीसरे चरण में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और अपने गणना फॉर्म भरे. एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल पात्र मतदाता ही शामिल हों और किसी भी अप्राप्त व्यक्ति का नाम न रहे. आयोग ने आगे कहा कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए एसआईआर अभ्यास के पहले दो चरणों में संबंधित एसआईआर आदेश जारी होने की तारीख तक लगभग 59 करोड़ मतदाता शामिल थे. इसमें कहा गया है कि इन चरणों के दौरान प्रक्रिया के अलग-अलग स्तरों पर 6.3 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी और 9.2 लाख बूथ लेवल एजेंट को तैनात किया गया था.

विश्वास मत से रोकना आपत्तिजनक : सुप्रीम कोर्ट

► सुको ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

► एक वोट से जीते विधायक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

नई दिल्ली, 14 मई. उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें नव निर्वाचित तमिलनाडु वेजी कषगम (टीवीके) विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति को तमिलनाडु विधानसभा में किसी भी विश्वास मत के प्रस्ताव पर मतदान करने से रोक दिया गया था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ,

न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश तथा मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए कहा कि यह आदेश कम से कम कहें, तो बेहद आपत्तिजनक है।मद्रास उच्च न्यायालय ने यह आदेश पराजित उम्मीदवार केआर पेरियाकरप्पन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका पर पारित किया था।उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चुनाव परिणाम को केवल चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने स्वयं यह माना था कि चुनाव याचिका ही उचित उपाय है.

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला फैसले को सुरक्षित रखा

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर महिलाओं की एंट्री के मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रखा. वीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में 9 जजों की बेंच ने केंद्र, धार्मिक संगठनों और याचिकाकर्ताओं की 16 दिन तक चलने वाली दलीलों को सुना. सुनवाई का मुख्य फोकस महिलाओं की मासिक घर्म आवृण्ण की 10 से 50 साल की महिलाओं की मंदिर में एंट्री विवाद रहा। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने महिलाओं पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक बताते हुए हटा दिया था।

भारत में इलेक्ट्रिक बसें तेजी से बढ़ेंगी

► वित्त वर्ष 35 तक वार्षिक विक्री में हिस्सेदारी 35-40 प्रतिशत तक

► सार्वजनिक परिवहन में ईवी बसों की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत

नई दिल्ली, 14 मई.भारत में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या और हिस्सेदारी आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ेगी. केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 35 तक इलेक्ट्रिक बसों की वार्षिक बिक्री में हिस्सेदारी 35-40 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जबकि सार्वजनिक परिवहन में ई-बसों की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत से

अधिक हो सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अब तक मार्च 2026 तक लगभग 16,300 इलेक्ट्रिक बसें चल रही थीं, जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक सरकारी टेंडर और सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों के माध्यम से तैनात की गई थीं। भारत में अब तक लगभग 62,000 ई-बस टेंडर जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 46,000 बसें विभिन्न सरकारी बसों के तहत आवंटित की गई हैं।केपीएमजी इंडिया के ऑटोमोटिव पार्टनर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लीड रोहन राव ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें

केवल नीतिगत पहल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह व्यापक मोबिलिटी इकोसिस्टम का संरचनात्मक बदलाव हैं. सरकारी खरीद कार्यक्रमों, लागत में सुधार और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश ने सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण को मजबूत गति दी है.रिपोर्ट में आगे कहा गया कि घरेलू मैनुफैक्चरिंग, फाइनोसिंग इनोवेशन, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अतिरिक्त और परिचालन दक्षता को संयोजित करते हुए एक स्केलेबल इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा. यह न केवल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देगा.

कोरोना मौतों का आंकड़ा तीन गुना ज्यादा

► वैश्विक कोरोना मौतों पर डब्ल्यूएचओ का खुलासा

जिनेवा, 14 मई. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से दुनिया भर में मौतों की वास्तविक संख्या 2.2 करोड़ से अधिक पहुंच गई है, जो आधिकारिक तौर पर दर्ज 70 लाख मौतों से करीब तीन गुना ज्यादा है. डब्ल्यूएचओ की बुधवार को जारी वर्ल्ड हेल्थ



स्टैटिस्टिक्स 2026 रिपोर्ट में कहा गया, वर्ष 2020 से 2023 के बीच सभी कारणों से वैश्विक अतिरिक्त मौतों (एक्ससेड्यूस) का अनुमान 2.21 करोड़ लगाया गया, जबकि कोविड-19 से आधिकारिक तौर पर 70 लाख मौतें दर्ज की गईं.

लोकार्पण 26 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 35 वर्षों के अनुभवों पर आधारित है 'अपनापन'

शिवराज की किताब में दिखेंगे मोदी के रंग

नई दिल्ली, 14 मई. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के अनुभवों पर आधारित पुस्तक 'अपनापन' लिखी है. दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस पुस्तक की घोषणा करते हुए कहा कि यह कृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीन दशक से अधिक के निकट संयोग, संगठनात्मक जीवन, जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रसमर्पण की जीवंत अनुभवों का सारा है, जिन्हें उन्होंने बहुत करीब से जिया है.



पुस्तक का लोकार्पण 26 मई 2026 को प्रातः 10:30 बजे नई दिल्ली स्थित एनएएस कॉम्प्लेक्स, पूसा में पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी.

देवगौड़ा द्वारा किया जाएगा. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह पुस्तक पाठकों को प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व, नेतृत्व, संवेदनशीलता और कार्यशैली को अधिक आत्मीयता से समझने का

अवसर देगी. उन्होंने कहा कि 'अपनापन' उनके उन अनुभवों, भावनाओं, प्रेरणाओं और जीवन मूल्यों को शब्द देती है, जिन्हें उन्होंने सार्वजनिक जीवन के लंबे सफर में नरेंद्र मोदी के साथ रहते हुए महसूस किया. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका संबंध 35 वर्षों से भी अधिक पुराना है.1991 की एकता यात्रा से शुरू हुआ यह साथ संगठनात्मक कार्यकर्ता के रूप में प्रारंभ हुआ और आगे चलकर मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री के रूप में विभिन्न जिम्मेदारियों में उनके साथ काम करने का अवसर मिला.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को एक निर्णायक और प्रभावशाली नेता के रूप में देखती है, लेकिन उन्होंने उनमें एक साधक, कर्मयोगी और राष्ट्रहित के लिए पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व को बहुत करीब से देखा है. उन्होंने कहा कि मोदी दर रात तक काम करने के बाद भी अगले दिन उसी ऊर्जा, स्पष्टता और प्रतिबद्धता के साथ देश के लिए खड़े दिखाई देते हैं. एकता यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय कुछ लोग उसे केवल राजनीतिक यात्रा मानते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे राष्ट्रीय चेतना के अभियान में बदल दिया.

► भैंसाकुंड घाट पर दी श्रद्धांजलि

लखनऊ, 14 मई.प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार लखनऊ के भैंसाकुंड घाट पर संपन्न हुआ, जहां परिवार, राजनीतिक हस्तियों और स्थानीय लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव को अपर्णा के अंतिम अंतिम दिवस ने मुखाग्नि दी.

प्रतीक की अर्था को शिवपाल के बेटे आदित्य यादव समेत परिवार के कई सदस्य ने कंधा दिया।प्रतीक यादव की



अंतिम यात्रा में पत्नी अपर्णा यादव और दोनों बेटियां भी मौजूद रहीं. उनके पार्थिव शरीर को पहले विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर रखा गया, ताकि लोग उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें. इस दौरान डिप्टी सीएम बूजेश पाठक और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे. स्वाभाव से मृदुभाषी प्रतीक यादव का जीवन परिवार और

राजनीतिक घटनाओं के बीच संतुलन बनाते हुए बीता. मुलायम सिंह यादव की मृत्यु और सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत हमलों के बाद वह काफी आहत हुए और कुछ समय के लिए गुमसुम भी रहने लगे. उनके निधन ने परिवार और समाज में शोक की लहर पैदा कर दी. प्रतीक की अंतिम यात्रा की गाड़ी खासतौर पर सजाई गई थी.